विनायक नारायण देवस्थली

बनाम

सी बी आई

(आपराधिक अपील सं. 346/2004)

02 दिसंबर, 2014

[सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और आदर्श कुमार गोयल, न्यायाधिपतिगण]

विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) अधिनियम, 1992 : धारा 10 - कुछ दलालों की मिलीभगत से ऐसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संबंधित सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप - अपीलकर्ता-बैंक प्रबंधक को धारा 120-बी, 409, 467, 471 आईपीसी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(सी) और (डी) के तहत विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया। - अभिनिर्धारित किया गया : अपीलकर्ता की कार्रवाई में सार्वजनिक धन का किसी व्यक्ति के निजी धन में अनधिकृत रूपांतरण शामिल था - आपराधिक मामला इस तथ्य से स्थापित किया गया था कि झूंठी बैंक रसीदे गैर-मौजूद प्रतिभूतियों के लिए जारी की गईं - अपीलकर्ता द्वारा जालसाजी/जाली दस्तावेजों का उपयोग करके सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, विश्वास के आपराधिक उल्लंघन

के साथ-साथ पीओसी अधिनियम के तहत अपराध है - दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।

न्यायालय ने अपील का निस्तारण निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित किया : तथ्य निर्विवाद हैं और स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर स्थापित हैं: (1) ईईपीसी इंजीनियरिंग वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में मदद करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रण में काम कर रहा है। यह घरेलू निर्यातकों के लिए स्टील की कीमत को बेअसर करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना संचालित कर रहा था। यह संवितरण के लिए धनराशि का विज्ञापन करता है। इसके अलावा इसके पास कार्यालय की बिक्री के लिए भी धन था। आईपीआरएस का संचालन पीडब्ल्यू द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने यूको बैंक के पक्ष में तीन चेक के माध्यम से यूको बैंक में 7.75 करोड़ रुपये की राशि जमा की। (II) यूको बैंक के सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाले अपीलकर्ता ने मेहता के खाते में राशि हस्तांतरित की, जो स्पष्ट रूप से ईईपीसी द्वारा किसी भी अधिकार के बिना मेहता के साथ मिलीभगत थी। उन्होंने ऐसी प्रतिभूतियों के अस्तित्व में आए बिना प्रतिभूतियों की भौतिक डिलीवरी के बदले में बैंक रसीदें जारी कीं। (iii) ईईपीसी ने कभी भी मेहता के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद का निर्देश नहीं दिया और न ही मेहता को संबंधित राशि के हस्तांतरण की अनुमति दी, लेकिन अपीलकर्ता के कहने पर ईईपीसी को गलत बेलफ के तहत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।

पीडब्लू-3, जिसने ईईपीसी का प्रतिनिधित्व किया, ने बैंक के पास जमा करने और किसी निजी पक्षकार के पक्ष में उक्त राशि के हस्तांतरण को अधिकृत नहीं करने के अभियोजन संस्करण का पूरी तरह से समर्थन किया। उक्त साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है। अपीलकर्ता ने मेहता के साथ साजिश कर अपने पद का दुरुपयोग कर अनाधिकृत रूप से मेहता के खाते में राशि जमा की। आरोपी ने प्रतिभूतियों के भौतिक अस्तित्व के बिना सुरक्षा लेनदेन के लिए बैंक रसीदें भी जारी कीं जो जालसाजी की श्रेणी में आती हैं। इस प्रकार, यह अनुमान लगाना सुरक्षित है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने मेहता के साथ साजिश रचकर और उनके लाभ के लिए पद का दुरुपयोग किया है। अभियुक्तों द्वारा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग जालसाजी/जाली दस्तावेजों का उपयोग करके आपराधिक विश्वासघात के साथ-साथ भ्रष्टाचार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध है। पीडब्लू-10 और पीडब्लू-12, जो प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के लिए रजिस्टर का रखरखाव कर रहे थे, यह नहीं दिखा सके कि प्रश्नगत प्रतिभूतियां बैंक के पास भौतिक रूप से उपलब्ध थीं, जब बैंक रसीदें आरोपी द्वारा जारी की गई थीं, जो केवल तभी किया जा सकता था जब प्रतिभूतियां उपलब्ध थीं। इस प्रकार विशेष न्यायालय ने आरोप को सही साबित किया। यह साबित करना जरूरी नहीं था कि आरोपी ने बैंक को कोई फायदा पहुंचाया या कोई नुकसान पहुंचाया। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता की कार्रवाई में सार्वजनिक धन का किसी व्यक्ति के निजी धन में अनधिकृत

रूपांतरण शामिल था। प्रतिभूतियों के अस्तित्व के बिना प्रतिभूतियो के लिये बैंक रसीदें जारी करना किसी निजी व्यक्ति को अवैध लाभ पहुंचाना उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अभ्यास या उच्च अधिकारियों के निर्देश के नाम पर पेटेंट अवैधता का बचाव नहीं किया जा सकता है। आपराधिक मामला इस तथ्य से स्थापित होता है कि गैर-मौजूद प्रतिभूतियों के लिए झूठी बैंक रसीदें जारी की गईं। इस प्रकार, साजिश, जालसाजी, हेराफेरी और भ्रष्टाचार के अपराध स्थापित होते हैं। [पैरा 14, 15 और 16] [332-ए-एच; 333-ए, ई]

राम नारायण पोपली बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2003) 3 एससीसी 641: 2003 (1) एससीआर 119 - पर भरोसा व्यक्त किया

केस कानून संदर्भ:

2003 (1) एससीआर 119 भरोसा व्यक्त किया पैरा 4

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 346/2004

केस नंबर 1/1997 में आर.सी. क्रमांक 9 (बीएससी)/94/बीओएम में विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) अधिनियम, 1992 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.01.2004 से

कामिनी जयसवाल, धीरज मिराजकर, एस. अल्ताफ, अपीलकर्ता के लिये।

चेतन चावला, टी.ए. खान, बी.वी. बलरामदास, अरविंद कुमार शर्मा, प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय आदर्श कुमार गोयल, न्यायाधिपति के द्वारा सुनाया गया। 1. यह अपील विशेष प्रकरण संख्या 1/1997 अंतर्गत आरसी नंबर 9 (बीएससी)/94/बीओएम में उक्त अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा पारित किया गये 20 जनवरी 2004 के फैसले और आदेश के खिलाफ विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) अधिनियम, 1992 (संक्षेप में "विशेष न्यायालय") की धारा 10 के तहत दायर की गई है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा श्री जानकी रमन की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर, ऐसे बैंकों और संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा कुछ सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संबंधित सार्वजनिक धन के अनधिकृत विचलन के आरोप की जांच के लिए कुछ दलालों के साथ मिलीभगत करके, 1 अप्रैल, 1991 से 6 जून, 1992 की अवधि के दौरान लेनदेन के संबंध में आपराधिक अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत के गठन के लिए अधिनियम बनाया गया था जैसा कि अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य कथित तौर पर सुरक्षा

लेनदेन में लगाए गए सार्वजनिक धन की शीघ्र वसूली करना और दोषियों को दंडित करना और बैंकों और वित्तीय संस्थाओ क्षेत्र में विश्वास और विश्वसनीयता बहाल करना था।

3. विशेष न्यायालय को अधिसूचित व्यक्तियों पर अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाना था। ऐसे नामित व्यक्तियों में से एक दलाल हर्षद एस मेहता था, जिसकी मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा का सहायक प्रबंधक था, जिस पर मेहता के साथ संयुक्त रूप से इस आरोप में मुकदमा चलाया गया था कि 12 मार्च, 1991 से 24 अप्रैल, 1991 की अवधि के दौरान, उसने इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (संक्षेप में "ईईपीसी) हर्षद एस. मेहता के निजी खाते में 7.75 करोड़ रुपये की राशि के फंड को डायवर्ट किया था"। यद्यपि उक्त धनराशि वापस ईईपीसी को हस्तांतरित कर दी गई थी, लेकिन अपीलकर्ता का आचरण भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 409, 467, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 धारा 13(1)(सी) और (डी) के तहत अपराध था।

4. विशेष न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध माना गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिवंगत मेहता के खाते में धन के हेरफेर से जुड़े पांच अन्य लेनदेन के संबंध में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के लिए विशेष अदालत द्वारा अपीलकर्ता की सजा को पहले इस अदालत ने आपराधिक अपील संख्या 1141/1999 में बरकरार रखा था, जिसका निर्णय

14 जनवरी 2003 को हुआ, राम नारायण पोपली बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो में प्रकाशित किया गया। हमें इस अदालत में आपराधिक अपील संख्या 687/2006 और आपराधिक अपील संख्या 335/2005 दाखिल करने के अलावा दो अन्य मामलों में विशेष अदालत द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराए जाने का भी संदर्भ मिलता है।

5. वर्तमान मामले में, विशेष न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप इस प्रकार हैं:

"पहला: कि अगस्त, 1990 से अप्रैल 1991 की अवधि के दौरान, आप ऊपर नामित आरोपी, सहायक प्रबंधक, यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के रूप में कार्यरत थे, ने हर्षद शांतिलाल मेहता, मूल आरोपी नंबर 1 (मृतक), एक शेयर, स्टॉक और सिक्योरिटीज ब्रोकर, मुंबई, जिसका उद्देश्य अवैध रूप से इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) के फंड को 7.75 करोड़ रुपये की सीमा तक पूर्वोक्त हर्षद के चालू खाता संख्या 1028 में स्थानांतरित करना था। शांतिलाल मेहता (मृतक), मैसर्स हर्षद एस. मेहता के नाम पर यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई में रखा गया है, और इस प्रकार आपके द्वारा उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) को अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया है। ऊपर नामित आरोपी ने प्रतिभूति लेनदेन की आड़ में भ्रष्ट या अवैध तरीकों से एक लोक सेवक के रूप में आपकी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया, इसे छिपाया जैसे कि लेनदेन यूको बैंक

के थे, जबकि यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण था कि लेनदेन वास्तव में उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता के थे और आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत और मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया है।

दूसरी बात: उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में और उसी लेन-देन के दौरान, 123, 1991 को या उसके आसपास, उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) ने, यूको बैंक के दलाल के रूप में कार्य करने का दावा करते हुए, बेईमानी से ईईपीसी, मुंबई को दो अनुबंध नोट जारी किए, जिसमें 22.3.1991 को उनकी ओर से समान प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए रेडी फॉरवर्ड आधार पर 14,4585 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1964 वर्ग की 692 लाख इकाइयों की खरीद दिखाई गई। 14,50628 प्रति यूनिट के साथ-साथ ईपीसी को झूठे डिलीवरी आदेश भी जारी किए और उन्हें यूको बैंक से उपरोक्त प्रतिभूतियों की डिलीवरी प्राप्त करने का निर्देश दिया और ईईपीसी को उक्त प्रतिभूतियों को जानने या विश्वास करने का कारण जानने के लिए यूको बैंक को सम तारीख का एक और डिलीवरी ऑर्डर भी जारी किया। उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) के कारण और उक्त साजिश को आगे बढ़ाने और उसी लेनदेन के दौरान यूको बैंक के पास ऐसी कोई प्रतिभूति नहीं होने के कारण ईईपीसी को उक्त प्रतिभूतियां वितरित नहीं कर सका ,आप ऊपर नामित अभियुक्त हैं, एक लोक सेवक होने के नाते, और आपको यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के नियंत्रण में या उसके तहत धन या

प्रभुत्व सौंपा गया था, ने बेईमानी से 12.03.1991 को एक कॉस्ट मेमो जारी किया था। यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि यूको बैंक का ईईपीसी के साथ ऐसा कोई लेन-देन नहीं था, उक्त प्रतिभूतियों की कुल राशि 99,99,988.20 रुपये में बिक्री की गई और यूको का बीआर नंबर 111/91 जारी करके जालसाजी का अपराध भी किया गया। उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) के निर्देशों पर बैंक ने यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि यह गलत दस्तावेज है, उक्त बीआर पर धोखे से हस्ताक्षर करके और जारी करके, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उक्त बीआर समर्थित नहीं था। प्रतिभूतियों, और उसके विचार में यूको बैंक के पक्ष में जारी किए गए 1 करोड़ रुपये के लिए ईईपीसी से भारतीय स्टेट बैंक, कफ परेड शाखा, मुंबई पर दिनांक 12.03.1991 को जारी बैंकर्स चेक संख्या 054053 प्राप्त करने के पक्ष में अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया। उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) ने बिना किसी सार्वजनिक हित के उक्त चेक की आय को सीधे हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) के नाम पर चालू खाता संख्या 1028 मेसर्स हर्षद एस. मेहता के नाम पर यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के साथ जारीकर्ता बैंक की ओर से बिना किसी निर्देश के में जमा करके आपराधिक कदाचार किया, और उक्त आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने में और उसी लेनदेन के दौरान ऊपर नामित आरोपी ने बेईमानी से उक्त राशि का क्रेडिट प्राप्त किया, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण कि यह चोरी की

संपत्ति है, अर्थात संपत्ति जिसके संबंध में आपराधिक विश्वास उल्लंघन का अपराध किया गया था और आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ आईपीसी की धारा 409, 411, 467, 471 और भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(सी) और 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध किया था और मेरे संज्ञान में है।

तीसरा : उक्त आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में, - और उसी लेन-देन के दौरान, 12.03.1991 को या उसके आसपास, ऊपर नामित आरोपी ने, सहायक प्रबंधक, यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा मुंबई के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्य करते हुए, बेईमानी से और धोखाधड़ी से यूको बैंक कॉस्ट मेमो दिनांक 12.03 जारी किया। 1991 में 99,99,और फर्जी तरीके से 99,99,980.20 रुपये की कुल राशि के लिए उक्त प्रतिभूतियों की कथित बिक्री के संबंध में, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण होने पर कि यूको बैंक का ईईपीसी के साथ ऐसा कोई लेनदेन नहीं था और इसके अलावा, बेईमानी से यूको बैंक बीआर नंबर 111/91 जारी किया गया, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि यह प्रतिभूतियों के साथ समर्थित नहीं है, ईईपीसी का पक्ष लेना और ऊपर नामित अभियुक्तों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के साथ पठित धारा 120-बी के तहत और मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया है।

चौथा: उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में और उसी लेनदेन के दौरान, 12.3.1991 को या उसके आसपास आप ऊपर नामित आरोपी ने

ईईपीसी को अग्रेषित करके उपरोक्त जाली बीआर नंबर 111/91 का असली इस्तेमाल किया और आपने इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 467 के साथ पठित 471 के तहत और मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया है।

पाँचवाँ: कि उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में और उसी लेन-देन के दौरान, 12.03.1991 को या उसके आसपास, आप ऊपर नामित अभियुक्त हैं, एक लोक सेवक होने के नाते और सहायक प्रबंधक, यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के रूप में अपनी क्षमता से काम कर रहे थे, और ऐसी क्षमता में आपको सौंपा गया था यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के नियंत्रण में या उसके नियंत्रण में धन या प्रभुत्व के साथ, यूको बैंक को देय एक खाता आदाता बैंकर चेक संख्या 054053 प्राप्त किया है और भारतीय स्टेट बैंक, कफे परेड शाखा मुंबई पर 1 करोड़ रुपये की राशि के लिए आहरित किया गया है, इस तरह के ट्रस्ट के निर्वहन के तरीके को छूने वाले व्यक्त या निहित अनुबंध का उल्लंघन करते हुए, इसे सीधे हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) द्वारा संचालित चालू खाता संख्या 1028 में जमा किया गया। मेसर्स हर्षद एस. मेहता का नाम, यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई में, जारीकर्ता बैंक से इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त किए बिना, और इसके द्वारा आपने धारा 409 के साथ पठित धारा 120-बी भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध किया है। और मेरे संज्ञान में है।

छठा: उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में और उसी लेनदेन के दौरान, 12.03.1991 को या उसके आसपास, आप उपरोक्त आरोपी हैं, एक लोक सेवक होने के नाते, सहायक प्रबंधक, यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करके और भ्रष्ट या अवैध तरीकों से, भारतीय स्टेट बैंक से यूको बैंक को देय 1 करोड़ रुपये का अकाउंट पेयी बैंकर चेक नंबर 054053 प्राप्त किया, जो उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) के लिए बिना किसी सार्वजनिक हित के अनुचित रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया था, और उक्त चैक की आय को सीधे मैसर्स हर्षद एस. मेहता के नाम पर यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई में उक्त हर्षद लाल मेहता (मृतक) द्वारा संचालित चालू खाता संख्या 1098 में अवैध रूप से जारीकर्ता बैंक से इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त किये बिना, जमा करके आपराधिक कदाचार किया और आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी सपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध किया है, और मेरे संज्ञान में.

सातवां: उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में और उसी लेनदेन के दौरान, 12.03.1991 को या उसके आसपास, आप उपरोक्त अभियुक्त हैं, एक लोक सेवक होने के नाते, सहायक प्रबंधक, यूको बैंक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करके, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई को 1 करोड़ रुपये का अकाउंट पेयी बैंकर्स चेक नंबर 054053 प्राप्त हुआ, जो भारतीय स्टेट बैंक पर आहरित यूको बैंक को देय था, उसने उक्त चेक की

आय को सीधे वर्तमान नंबर 1028 में जमा करके उक्त धनराशि का बेईमानी से दुरुपयोग किया। उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) द्वारा, यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई में, मैसर्स हर्षद एस. मेहता के नाम पर, जारीकर्ता बैंक से इस संबंध में किसी भी निर्देश के बिना बनाए रखा गया था, और आपने इस प्रकार प्रतिबद्ध किया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी सपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा धारा 13(2) सपठित 13(1)(सी) के तहत दंडनीय अपराध किया, और मेरे संज्ञान में है।

आठवां: उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में और उसी लेनदेन के दौरान, 23.04.1991 को या उसके आसपास, उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक), यूको बैंक के लिए ब्रोकर के रूप में कार्य करने का दावा करते हुए, ईईपीसी, मुंबई को बेईमानी से दो अनुबंध नोट जारी किए गए, जिसमें उनकी ओर से 8.5.91 को 15, 11096 प्रति यूनिट और समान प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए रेडी फॉरवर्ड आधार पर 1500 रुपये प्रति यूनिट पर यूनिट्स 1964 योजना की 35 लाख इकाइयों की खरीद दिखाई गई और ईईपीसी को झूठे डिलीवरी ऑर्डर भी जारी किए, जिसमें उन्हें यूको बैंक से उपरोक्त प्रतिभूतियों की डिलीवरी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया और ईईपीसी को उक्त प्रतिभूतियों को जानने या विश्वास करने का कारण जानने के लिए यूको बैंक को सम तारीख का एक और डिलीवरी ऑर्डर भी जारी किया] यह जानते हुये या विश्वास करने का कारण रखते हुये कि यूको बैंक के पास उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) के खाते में ऐसी कोई

प्रतिभूतियाँ नहीं होने के कारण ईईपीसी को उक्त प्रतिभूतियाँ वितरित नहीं कर सका, और उक्त साजिश को आगे बढ़ाने में, और उसी के दौरान लेन-देन, आप ऊपर नामित आरोपी हैं, एक लोक सेवक होने के नाते, और आपको यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के नियंत्रण में या उसके तहत धन या प्रभुत्व सौंपा गया था, जिसके संबंध में बेईमानी से दिनांक 23.04.1991 को एक लागत ज्ञापन जारी किया गया था। यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि यूको बैंक का ईईपीसी के साथ ऐसा कोई लेन-देन नहीं था, उक्त प्रतिभूतियों की कुल 5.25 करोड़ रुपये की बिक्री की गई और उसने यूसीओ का बीआर नंबर 153/91 जारी करके जालसाजी का अपराध भी किया। उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) के निर्देश पर बैंक ने यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उक्त बीआर प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित नहीं था, उक्त बीआर पर धोखे से हस्ताक्षर करके और यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि यह गलत दस्तावेज है, उक्त बीआर जारी कर दिया और इसके विचार में, यूको बैंक के पक्ष में 5.25 करोड़ रुपये के लिए ईईपीसी से भारतीय स्टेट बैंक, कफ परेड शाखा, मुंबई पर आहरित बैंकर चेक संख्या 054337 दिनांक 23.04:1991 प्राप्त करके उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) के पक्ष में बिना किसी सार्वजनिक हित के अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया। और उक्त चेक की आय को सीधे हर्षद शांतिलाल मेहता द्वारा मैसर्स हर्षद हर्षद एस. मेहता के नाम से यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के साथ

संचालित चालू खाता संख्या 1028 में जारीकर्ता बैंक से इस संबंध में किसी भी निर्देश के बिना जमा करके आपराधिक कदाचार किया, और आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी सपठित धारा 409, 471 भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) सपठित 13(1)(सी) और 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध किया है और मेरे संज्ञान में है।

नौवां: वह उक्त आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में और उसी लेन-देन के दौरान, 23.04.1991 को या उसके आसपास, आप उपरोक्त नामित आरोपी ने सहायक प्रबंधक, यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्य करते हुए, बेईमानी से और धोखाधड़ी से यूको बैंक कॉस्ट मेमो दिनांक 23.04.91 को 5.25 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए उक्त प्रतिभूतियों की कथित बिक्री के संबंध में जारी किया यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि यूको बैंक का ईईपीसी के साथ ऐसा कोई लेनदेन नहीं था और आगे बेईमानी से यूको बैंक बीआर नंबर 153/91 जारी किया गया। ईईपीसी का पक्ष लेना या यह विश्वास करने का कारण होना कि यह प्रतिभूतियों के साथ समर्थित नहीं था और ऊपर नामित अभियुक्तों ने भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 120-बी सपठित धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध है और मेरे संज्ञान में है।

दसवां: उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में और उसी लेनदेन के दौरान, 23.04.1991 को या उसके आसपास, आप उपरोक्त नामित अभियुक्त

ने उपरोक्त जाली बीआर नंबर 153/91 को ईईपीसी को अग्रेषित करके वास्तविक के रूप में इस्तेमाल किया और कि आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी सपठित धारा 467 सपठित धारा 471 के तहत दंडनीय अपराध किया है और यह मेरे संज्ञान में है।

ग्यारहवां: उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में और उसी लेनदेन के दौरान, 23.04.1991 को या उसके आसपास, आप उपरोक्त नामित अभियुक्त ने, एक लोक सेवक होने के नाते और सहायक प्रबंधक, यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के रूप में काम कर रहे हैं, और ऐसी क्षमता में यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई को यूको बैंक से देय अकाउंट पेयी बैंकर्स चेक नंबर 054337 प्राप्त हुआ और इसे भारतीय स्टेट बैंक, कफ परेड शाखा, मुंबई से 5.25 करोड़ रुपये की राशि के लिए आहरित किया गया के नियंत्रण में या उसके तहत धन या प्रभुत्व सौंपा गया है, जो स्पष्ट या निहित अनुबंध का उल्लंघन है। इस तरह के ट्रस्ट के निर्वहन का तरीका, इसे सीधे यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई में मेसर्स हर्षद एस मेहता के नाम पर उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) द्वारा संचालित चालू खाता संख्या 1028 में जमा किया गया। जारीकर्ता बैंक से इस संबंध में किसी भी निर्देश के बिना, और इसके द्वारा आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 – बी सपठित धारा 409 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध किया है और यह मेरे संज्ञान में है।

बारहवाँ: वह उक्त आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में और उसी लेन-देन के दौरान, 23.04.1991 को या उसके आसपास, आप पर, जिसका नाम ऊपर नामित है, एक लोक सेवक होने के नाते, एक सहायक प्रबंधक, यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करके, एक खाता प्राप्तकर्ता प्राप्त किया। यूको बैंक को देय 5.25 करोड़ रुपये का बैंकर्स चेक संख्या 054337, जो भारतीय स्टेट बैंक से जारी किया गया था, ने उक्त चेक की आय को सीधे हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) द्वारा संचालित चालू खाता संख्या 1028 में मेसर्स हर्षद एस. मेहता के नाम पर यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई में जमा करके उक्त धनराशि का बेईमानी से दुरुपयोग किया, जारीकर्ता बैंक से इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त किए बिना, और इसके द्वारा आपने धारा 120-बी सपठित भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(1) सपठित धारा 13(2) के तहत दंडनीय अपराध किया है और मेरे संज्ञान में है।

तेरहवां: कि उक्त आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में और उसी लेन-देन के दौरान, 23.04.1991 को या उसके आसपास, ऊपर नामित अभियुक्त ने, एक लोक सेवक होते हुए, एक सहायक प्रबंधक, यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके, एक खाता प्राप्तकर्ता प्राप्त किया। 5.25 करोड़ रुपये का बैंकर चेक संख्या 054337, यूको बैंक को देय और भारतीय स्टेट बैंक, कफ परेड शाखा, मुंबई पर आहरित, उक्त चेक की आय को सीधे चालू खाता संख्या 1028 उक्त हर्षद

शांतिलाल मेहता (मृतक) द्वारा मेसर्स हर्षद एस. मेहता के नाम पर यूको बैंक हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई में जमा करते हुए बेईमानी से उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया, जारीकर्ता बैंक से इस संबंध में किसी भी निर्देश के बिना, और आपने रोकथाम की धारा 120-बी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) सपठित 13(1)(सी) सपठित धारा 120- बी के तहत दंडनीय अपराध किया है और मेरे संज्ञान में है।

चौदहवां: उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में और उसी लेनदेन के दौरान, 24.04.1991 को या उसके आसपास, उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक के बाद से), यूको बैंक के ब्रोकर के रूप में कार्य करने का दावा करते हुए, बेईमानी से अनुबंध जारी किया गया ईईपीसी, मुंबई को भेजे गए नोट, जिसमें उनकी ओर से 29.04.1991 को समान प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए 15.00 रुपये प्रति यूनिट पर यूनिट्स 1964 योजना की 10 लाख इकाइयों की खरीद को 15.04110 रुपये प्रति यूनिट पर दिखाया गया है, जो गलत भी जारी किया गया है, ईईपीसी को डिलीवरी ऑर्डर में यूको बैंक से उपरोक्त प्रतिभूतियों की डिलीवरी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया और एक और डिलीवरी ऑर्डर भी यूको बैंक को सम तारीख तक ईईपीसी को उक्त प्रतिभूतियाँ वितरित करनी होंगी, जारी किया गया, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण होने पर कि यूको बैंक उक्त प्रतिभूतियों को ईईपीसी को वितरित नहीं कर सका क्योंकि यूको बैंक के पास हर्षद लाल मेहता (मृतक) के कारण ऐसी कोई प्रतिभूतियां नहीं थीं और उक्त साजिश को आगे

बढ़ाने में, और उसी लेनदेन के दौरान, आप ऊपर नामित आरोपी हैं, एक लोक सेवक होने के नाते, और यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के नियंत्रण में या उसके अधीन धन या प्रभुत्व सौंपा गया था, उसने बेईमानी से उक्त प्रतिभूतियों की कुल राशि के लिए बिक्री के संबंध में दिनांक 24.04.1991 को 1.50 करोड़ का एक कॉस्ट मेमो जारी किया यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि यूको बैंक का ईईपीसी के साथ ऐसा कोई लेन-देन नहीं था और यह जानते हुए भी कि हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) के निर्देशों पर यूको बैंक के बीआर नंबर 16बी/91 को जारी करने में जालसाजी का अपराध किया या यह विश्वास करने का कारण होना कि यह झूठा दस्तावेज़ है, धोखाधड़ी से हस्ताक्षर करके और उक्त बीआर को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उक्त बीआर जारी किया गया है। बीआर को प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित नहीं किया गया था और उसके विचार में यूको बैंक के पक्ष में जारी किए गए 1 करोड़ रुपये के लिए ईईपीसी से भारतीय स्टेट बैंक, कफ परेड शाखा, मुंबई पर दिनांक 24.04.1991 को जारी बैंकर्स चेज नंबर 054353 प्राप्त हुआ था। उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) के लिए बिना किसी सार्वजनिक हित के अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया और उक्त चेक की आय को सीधे उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) द्वारा संचालित चालू खाता संख्या 1028 से मेसर्स हर्षद एस. मेहता के नाम यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई में जमा करके आपराधिक कदाचार किया, जारीकर्ता बैंक से इस संबंध में कोई निर्देश

प्राप्त किए बिना और यह कि आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी सपठित धारा 409, 467, 471 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित 13(1)(सी) और 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध किया है और मेरे संज्ञान में है।

पन्द्रहवाँ: कि उक्त आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में और उसी लेन-देन के दौरान, 24.04.1991 को या उसके आसपास, ऊपर नामित अभियुक्त ने, सहायक प्रबंधक, यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए, बेईमानी से और धोखाधड़ी से यूको बैंक कॉस्ट मेमो दिनांक 24.04.1991 को 1.50 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए उक्त प्रतिभूतियों की कथित बिक्री के संबंध में जारी किया, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि यूको बैंक का ईईपीसी के साथ ऐसा कोई लेनदेन नहीं था और आगे बेईमानी से ईईपीसी के पक्ष में यूको बैंक बीआर नंबर 168791 जारी किया गया, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि यह प्रतिभूतियों के साथ समर्थित नहीं था और ऊपर नामित अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी सपठित धारा 467 के तहत दंडनीय अपराध किया ओर मेरे संज्ञान में है।

सोलहवाँ: कि उक्त आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में और उसी लेन-देन के दौरान, 24.04.1991 को या उसके आसपास, ऊपर नामित आरोपी ने ईईपीसी को अग्रेषित करके उपरोक्त जाली बीआर नंबर 168/91 को वास्तविक के रूप में इस्तेमाल किया और इस तरह आपने भारतीय दंड

संहिता की धारा 120 - बी सपठित धारा 467, 471 के तहत दंडनीय अपराध किया और मेरे संज्ञान में है।

सत्रहवाँ: कि उक्त आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में 24.04.1991 को, आप ऊपर नामित आरोपी हैं, एक लोक सेवक होने के नाते और सहायक प्रबंधक, यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के रूप में काम कर रहे हैं, और ऐसी क्षमता में आपको धन या उसके तहत धन का प्रभुत्व सौंपा गया है या यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के नियंत्रण में, यूको बैंक को देय एक अकाउंट पेयी बैंकर्स चेक नंबर 054353 प्राप्त हुआ है और 1.50 करोड़ रुपये की राशि के लिए भारतीय स्टेट बैंक, कफ परेड शाखा, मुंबई को आहरित किया गया है, इस तरह के ट्रस्ट के निर्वहन के तरीके को छूने वाले व्यक्त या निहित अनुबंध का उल्लंघन करते हुए, इसे सीधे हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) द्वारा बनाए गए चालू खाता संख्या 1028 में मैसर्स हर्षद एस. मेहता के नाम यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के साथ जमा किया गया, जारीकर्ता बैंक से इस संबंध में किसी भी निर्देश के बिना और आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 120- बी सपठित 409 के तहत दंडनीय अपराध किया है, जो कि मेरे संज्ञान में है।

अठारहवाँ : कि उक्त आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में 24.04.1991 को, आप ऊपर नामित आरोपी हैं, एक लोक सेवक होने के नाते, सहायक प्रबंधक, यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करके और भ्रष्ट या अवैध तरीकों से यूको बैंक को देय

और भारतीय स्टेट बैंक पर आहरित 1.50 करोड़ रुपये का अकाउंट पेयी बैंकर्स चेक नंबर 054353 प्राप्त करते हुये, उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) के लिए बिना किसी सार्वजनिक हित के अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुये उक्त चेक की आय को अवैध रूप से मेसर्स हर्षद एस. मेहता के नाम पर यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई में उक्त हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) द्वारा संचालित चालू खाता संख्या 1028 में सीधे जमा करते हुये आपराधिक कदाचार किया, जारीकर्ता बैंक से इस संबंध में जारीकर्ता बैंक के किसी भी निर्देश के बिना, और इसके द्वारा आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी सपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध किया है और मेरे संज्ञान में है।

उन्नीसवां : यह कि उक्त आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में 24.04.1991 को आप उपरोक्त अभियुक्त ने, एक लोक सेवक होते हुए, आपने यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के सहायक प्रबंधक के आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके, उन्होंने 1.50 करोड़ रुपये का अकाउंट पेयी बैंकर चेक नंबर 054353 प्राप्त करते हुये, जो यूको बैंक को भारतीय स्टेट बैंक से देय था, उन्होंने बेईमानी से प्राप्त राशि को क्रेडिट करके उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया। उक्त चेक सीधे हर्षद शांतिलाल मेहता (मृतक) द्वारा यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई में मेसर्स हर्षद एस. मेहता के नाम से संचालित चालू खाता संख्या 1028 में जारीकर्ता बैंक से बिना किसी निर्देश के डाला गया और यह कि आपने भारतीय दंड संहिता की धारा-120बी,

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(सी) सपठित धारा 13(2) के तहत दंडनीय अपराध किया है, और यह मेरे संज्ञान में है।"

6. ईईपीसी की स्थापना वाणिज्य मंत्रालय के तहत इंजीनियरिंग वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना (संक्षेप में "आईपीआरएस") नामक एक योजना संचालित कर रहा था, जिसका उद्देश्य घरेलू निर्यात के लिए स्टील की कीमत को अंतरराष्ट्रीय बाजार के बराबर करना था, जहां कीमतें कम थीं। इस योजना में मूल्य अंतर की प्रतिपूर्ति के माध्यम से निर्यातकों को मुआवजा देने की परिकल्पना की गई थी। संयुक्त योजना समिति (जेपीसी") के माध्यम से ईईपीसी द्वारा प्राप्त धनराशि को कलकत्ता में भारतीय स्टेट बैंक के पास रखा गया था। पीडब्लू-3, ईईपीसी के एक अधिकारी गिरीश चंद्र इस योजना को चला रहे थे। उक्त निधि के अलावा, उपलब्ध अन्य स्रोत ईईपीसी के पास जो धनराशि थी, वह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किराए के परिसर में कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए टार्डी, मुंबई में परिसर की बिक्री थी, जिसे अधिक उपयुक्त माना जाता था। बिक्री आय भारतीय स्टेट बैंक, कफे परेड शाखा के पास रखी गई थी। बीच की अवधि के दौरान 12 मार्च, 1991 और 24 अप्रैल, 1991 को पीडब्लू-3 ने यूको बैंक के पक्ष में तीन चेक जारी किए, जहां अपीलकर्ता तैनात था। ईईपीसी के निर्देशों के बिना, उक्त राशि स्वर्गीय मेहता के निजी खाते में स्थानांतरित कर दी गई। हालांकि ईईपीसी को प्राप्त हुआ तीन लेनदेन के संबंध में

अनुबंध नोट और वितरण आदेश और दस्तावेजों पर पीडब्लू.3 द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे, लेकिन यह गलत सोच थी कि वह केवल बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षर कर रहा था। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने मेहता के साथ मिलीभगत करके अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक धन को अनधिकृत रूप से एक व्यक्ति के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रतिभूतियों की भौतिक डिलीवरी के बदले में बैंक द्वारा ईईपीसी को जाली बैंक रसीदें (बीआर) जारी की गईं, ऐसी प्रतिभूतियों के अस्तित्व में नहीं होने के बावजूद। पीडब्लू-4, अरूप मोहन पटनायक, सीबीआई के एक अधिकारी, ने जांच के बाद 30 नवंबर, 1994 को एफआईआर दर्ज की। जांच आगे पीडब्लू-13, श्री एस.के. सरीन, इंस्पेक्टर सीबीआई द्वारा की गई, जिन्होंने ईईपीसी, यूको बैंक और भारतीय स्टेट बैंक से दस्तावेज एकत्र किए और गवाहों के बयान भी दर्ज किए। उन्होंने दिवंगत मेहता और अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

7. दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के अलावा, अभियोजन पक्ष ने श्री छादिसिंह-पीडब्लू-1, श्री मैत्रा-पीडब्लू-2, श्री गिरीश चंद्र-पीडब्लू-3, श्रीमती सुधा कुबल-पीडब्लू-4, श्री अंकुर गुप्ता-पीडब्लू-5 और श्री बाबाजी फ़िरोज़-पीडब्लू-6, के मौखिक साक्ष्य पर भरोसा किया, ये सभी मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय में ईईपीसी के साथ विभिन्न क्षमताओं में काम कर रहे हैं; श्री बी.डी. राऊत-पीडब्लू-7; श्री आरसीवाला-पीडब्लू 8 भारतीय स्टेट बैंक के साथ कार्यरत; श्री अंजारिया-पीडब्लू-9; श्री पिंजानी-पीडब्लू-10 और नीलम

केनी-पीडब्लू-12 यूको बैंक, हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई में अलग-अलग पदों पर कार्यरत हैं... बाकी गवाह श्री जैन-पीडब्लू-11, हस्तलेखन विशेषज्ञ हैं; श्री पटनायक-पीडब्लू-14, जिन्होंने एफआईआर दर्ज की और श्री एस.के. सरीन-पीडब्लू-13 जांच अधिकारी हैं और उन्होंने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

अभियुक्तों ने बचाव साक्ष्य का नेतृत्व किया और डीडब्लू 1- श्री अतुल मनुभाई पारेख, जो प्रासंगिक समय में हर्षद मेहता के कार्यालय में काम कर रहे थे और श्री प्रदीप अनंत करखानिस- डीडब्लू -2, जो यूको बैंक में प्रासंगिक समय पर वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे, को परीक्षित कराया।

8. अपीलकर्ता का पक्ष यह है कि स्वर्गीय मेहता के खाते में जमा राशि अपीलकर्ता के बेईमान इरादे के कारण नहीं थी। बैंक दलालों को कमीशन लेकर सुरक्षा लेनदेन की सुविधा दे रहा था। लेनदेन दलालो और विपक्षी पक्षकारो के बीच थे। सभी दस्तावेज़ बैंकिंग के सामान्य तरीके से तैयार किए गए थे।

9. विशेष अदालत ने अभियुक्तों के बचाव को खारिज कर दिया और माना कि दिवंगत मेहता के निजी खाते में धनराशि का हस्तांतरण ईईपीसी द्वारा किसी प्राधिकरण के बिना किया गया था। यह माना गया :

"इस संबंध में सभी सबूतों को चुनौती नहीं दी गई है। हालांकि, आरोपी का बचाव यह है कि यूको बैंक की हमाम स्ट्रीट शाखा ग्राहकों की ओर से इस तरह के प्रतिभूति लेनदेन कर रही थी और यह 1987 से चल रहा था, उसके 1989 में उक्त शाखा में शामिल होने से बहुत पहले से । उनके अनुसार अठारह दलालों को ऐसी नियमित सुविधा मिल रही थी। यह सुविधा मई, 1991 और मार्च, 1992 के बीच की अवधि के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी और मार्च, 1992 में दलालों को इसी तरह की सुविधा दी जाती रही। उनका बचाव यह है कि उपरोक्त तीन लेनदेन ईईपीसी और एचएसएम के बीच थे। यूको बैंक को कभी कोई अनुबंध नोट नहीं भेजा गया था। प्रधान कार्यालय को ऐसे लेनदेन के बारे में पता था। यह स्वीकार करते हुए कि उपरोक्त तीन लेनदेन से संबंधित सभी वाउचर, लागत मेमो और बीआरएस उनकी शाखा में उनके कहने पर तैयार किए गए थे। उनका बचाव यह है कि ये बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए थे। उनका कहना है कि वह निर्दोष हैं और बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

आरोपी के खिलाफ आरोप यह है कि उसने बेईमानी और धोखाधड़ी के इरादे से ईईपीसी के फंड, सार्वजनिक धन को एचएसएम में स्थानांतरित करने के लिए एचएसएम के साथ साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य एचएसएम को ऐसे डायवर्ट किए गए धन का लाभ

पहुंचाना था। आरोपी के खिलाफ यह भी आरोप है कि उसके पास यूको बैंक के पक्ष में एसबीआई द्वारा जारी किए गए उपरोक्त तीन बैंकर्स चेक की राशि को एचएसएम के खाता संख्या 1028 में जमा करने के लिए ईईपीसी या बैंक अधिकारियों से कोई अधिकार नहीं था। और, इसलिए, आरोपी ने लोक सेवक अर्थात्, मुंबई में यूको बैंक की हमाम स्ट्रीट शाखा के प्रतिभूति विभाग में प्रबंधक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था।

आरोपी पर इन लेनदेन के संबंध में ऐसे बीआर जारी करने के लिए भौतिक प्रतिभूतियों के समर्थन के बिना बीआर जारी करने का भी आरोप है और इसलिए, यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने लागत मेमो और बीआरएस जैसे दस्तावेजों को जाली बनाकर तैयार किया था उन्हें वास्तविक के रूप में उपयोग किया था।

चूंकि तीनों लेन-देन उपरोक्त तरीके से हुए साबित हुए हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि ईईपीसी ने अपने अल्पकालिक निवेश के उद्देश्य से अपने फंड को एसबीआई में अपने खाते से यूको बैंक में स्थानांतरित कर दिया था। गिरीश चंद्र-पीडब्ल्यू 3 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों और परिपत्रों के अनुसार, उन्हें ईईपीसी के अधिशेष धन का निवेश या तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में या सरकारी प्रतिभूतियों या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में करने का अधिकार था और वह एचएसएम सहित किसी भी व्यक्ति

के लाभ के लिए ईईपीसी के फंड को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था। उपरोक्त लेनदेन से, यह स्पष्ट है कि यूको बैंक के पक्ष में जारी किए गए सभी तीन बैंकर्स चेक एचएसएम के खाते में जमा किए गए थे, खाता संख्या 1028 है। लेनदेन से यह भी पता चलता है कि आरोपी ने ईईपीसी के खिलाफ उसमें दिखाए गए प्रतिभूतियों की बिक्री के लेनदेन के लिये लागत ज्ञापन जारी किया था। जब चेक प्राप्त हुए तो राशि एचएसएम के खाते में जमा कर दी गई। एचएसएम द्वारा यूको बैंक को जारी किए गए डिलीवरी नोट्स के तहत निर्देश थे कि यूको बैंक को ईईपीसी को 1964 योजना के अनुसार निश्चित संख्या में यूनिट्स वितरित करनी चाहिए, जैसा कि डिलीवरी ऑर्डर में दिखाया गया है, यूको बैंक को संकेतित दरों पर। इसलिए, आरोपी ने एचएसएम के निर्देशों के अनुसार काम किया था। हालाँकि, यह एचएसएम द्वारा ईईपीसी को जारी किए गए अनुबंध नोट्स के विपरीत था, जिसमें स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि सभी तीन लेनदेन में एचएसएम ब्रोकर के रूप में कार्य कर रहा था। अनुबंध नोट में संकेत यह है कि एचएसएम ने ईईपीसी के लिए और उसकी ओर से 1964 योजना की कुछ निश्चित संख्या में इकाइयाँ खरीदी थीं और ईईपीसी और यूको बैंक को जारी किए गए डिलीवरी ऑर्डर से संकेत मिलता है कि ईईपीसी को यूको बैंक से उक्त इकाइयाँ प्राप्त करनी हैं और यूको बैंक ने उन इकाइयों को ईईपीसी को सौंपना

था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एचएसएम ब्रोकर के रूप में कार्य कर रहा था और वह उन लेनदेन का प्रमुख या प्रतिपक्ष नहीं था। फिर भी, यूको बैंक ने एचएसएम को प्रमुख यानि कि विपक्षी पक्षकार के रूप में माना था ईईपीसी से सीधा संपर्क होने के कारण। इसलिए, आरोपी ने ईईपीसी की ओर से एसबीआई से प्राप्त राशि को एचएसएम के खाते में जमा कर दिया। किसी भी घटना में, एसबीआई, खाता ईईपीसी पर आहरित बैंकर्स चेक वास्तव में केवल यूको बैंक के पक्ष में थे, किसी अन्य पार्टी के पक्ष में नहीं। इसलिए, आरोपी उन तीन चेकों के तहत उन रकमों को केवल यूको बैंक खाते में ही जमा कर सकता था, किसी और के खाते में नहीं। जाहिर तौर पर इस संबंध में ईईपीसी की ओर से कोई निर्देश नहीं थे। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से ईईपीसी के फंड को अवैध रूप से एचएसएम के खाते में स्थानांतरित करने और एचएसएम को अनुचित आर्थिक लाभ देने में आरोपी और एचएसएम की मिलीभगत को दर्शाता है। इसलिए, अभियोजन पक्ष ने स्थापित किया है कि यह दोनों के बीच एक आपराधिक साजिश है, जिसका उद्देश्य अवैध रूप से ईईपीसी के धन को स्थानांतरित करना था, जो कि खाता संख्या 1028 में एचएसएम के चालू खाते में पूरी तरह से 7.75 करोड़ रुपये था, जिससे एचएसएम ने इसका अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया जा सके और आरोपी ने लेनदेन को प्रतिभूतियों के

लेनदेन के रूप में छिपाकर लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया था।

यह भी स्थापित किया गया है कि आरोपी ने प्रतिभूतियों की भौतिक डिलीवरी के बदले में बीआर जारी किए, जबकि बैंक के पास प्रतिभूतियां बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थीं। यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है कि बीआर भौतिक प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित नहीं थे। हालाँकि, यह एक नकारात्मक बोझ है जिसका निर्वहन किया जाना चाहिए और इसलिए यह वहन किये जाने के लिये हल्का बोझ है। गवाहों अर्थात् पीडब्लू 10 पिंजानी और श्रीमती किनी-पीडब्लू 12 ने कहा है कि वे प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के लिए -रजिस्टर बनाए रखते थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि जब आरोपियों द्वारा लागत मेमो और बीआरएस जारी किए गए थे तो बैंक के पास भौतिक रूप से प्रतिभूतियां उपलब्ध थीं। जांच अधिकारी ने बैंक के पास भौतिक रूप से कोई प्रतिभूति उपलब्ध नहीं होने की बात कही है। अंजारिया-पीडब्लू 9 के साक्ष्य यह भी इंगित करते हैं कि यूनिट्स 1964 योजना का कोई भी रजिस्टर सुरक्षा-वार या ब्रोकर ग्राहक-वार नहीं रखा गया था। इसने उन प्रतिभूतियों के अस्तित्व को स्थापित नहीं किया जहां आरोपियों ने उन्हें समर्थन देने के लिए बीआर जारी किए थे। उपरोक्त साक्ष्य बोझ उतारने के लिए पर्याप्त है। यह ध्यान रखना उचित है कि यहां तक कि यह भी बचाव नहीं है कि

बीआरएस का समर्थन करने के लिए भौतिक प्रतिभूतियां उपलब्ध थीं। इसलिए, यह स्थापित हो गया है कि बीआर भौतिक प्रतिभूतियों के समर्थन के बिना और भौतिक प्रतिभूतियों के बदले में जारी किए गए थे।

यह निर्विवाद स्थिति है कि एचएसएम प्रतिभूतियों में काम कर रहा था। डीडब्ल्यू 1 अतुल पारेख ने तीनों लेनदेन के संबंध में एचएसएम के कार्यालय से डिलीवरी ऑर्डर जारी किए जाने के बारे में बात की है और वे एचएसएम के लेनदेन थे। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदर्श ए-2(3) में पत्र गिरीश चंद्र-पीडब्लू 3 द्वारा पंकज शाह को लिखा गया था, इस पत्र के साथ उन्होंने यूको बैंक के पक्ष में 1 करोड़ रुपये के बैंकर्स चेक भी भेजे थे। गिरीश चंद्र – पीडब्लू 3 ने यह पत्र लिखने की बात स्वीकार की है। हालाँकि, उनका कहना है कि चेक यूको बैंक के पक्ष में जारी किया गया था, एचएसएम के पक्ष में नहीं। पत्र दिनांक 11.3.1991 को पंकजशाह और गिरीश चंद्र पीडब्लू 3 के बीच दिनांक 12.3.1991 और 22.3.1991 के बीच 14 प्रतिशत की दर से 1 करोड रूपये के निवेश के बारे मे चर्चा को बताता है। पत्र में दिनांक 22.3.1991 को लेनदेन के उलट होने का भी उल्लेख है और अर्जित ब्याज के साथ बैंकर्स चेक वापस भेजना बताया है। अभियुक्त की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि इससे संकेत मिलता है कि लेनदेन ईईपीसी और एचएसएम के बीच विरोधी पक्षकार के रूप में था।

हालाँकि, तथ्य यह है कि 1 करोड़ रुपये का चेक एचएसएम के पक्ष में जारी नहीं किया गया था, बल्कि यह यूको बैंक के पक्ष में ही जारी किया गया था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ईईपीसी ने एचएसएम के खाते में एक करोड़ रुपये की राशि डेबिट करने के लिए यूको बैंक को कोई निर्देश जारी नहीं किया था। इन विवरणों के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि एचएसएम विरोधी पक्षकार या प्रमुख था जिसके साथ ईईपीसी का सीधा लेनदेन था। इसके विपरीत इसमें संकेत दिया गया कि एक करोड़ रुपये के चेक का भुगतान यूको बैंक को किया जाना था। यदि यह हो तो; ऐसा है, अधिक से अधिक एचएसएम को केवल दलाल ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं। फिर भी आरोपी ने इन तीन लेनदेन के संबंध में चेक प्राप्त करने पर एचएसएम के खाते में राशि जमा की, जो पूरी तरह से अवैध था।

इन परिस्थितियों में, आरोपी तीन चेक की राशि केवल यूको बैंक के खाते में जमा कर सकता था, एचएसएम के खाते में नहीं। इस संबंध में अभियुक्त की ओर से भी पुरजोर तरीके से कहा गया कि गिरीश चंद्र द्वारा एचएसएम के कार्यालय में कार्यरत पंकज शाह को लिखे गये पत्र दिनांक 12.3.1991 से संकेत मिलता है कि गिरीश चंद्र - पीडब्लू 3 और एचएसएम के बीच उनके अल्पकालिक निवेश के संबंध में कुछ बातचीत हुई थी और उक्त दो लेनदेन के संबंध में भी

ऐसा प्रतीत होता है दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। फिर भी, यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उस मामले के लिए ईईपीसी या गिरीश चंद्र-पीडब्लू 3 ने एचएसएम के साथ एक प्रतिपक्षी या प्रमुख के रूप में सीधे व्यवहार किया था। ईईपीसी द्वारा एसबीआई के माध्यम से जारी किए गए सभी बैंकर्स चेक अकेले यूको बैंक के पक्ष में थे, एचएसएम के खाते में उन राशियों को जमा करने के लिए यूको बैंक को कोई और निर्देश दिए बिना। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ईईपीसी ने काउंटर पार्टी के रूप में एचएसएम के साथ सीधा लेनदेन किया था। ऐसा होने पर, आरोपी के पास ईईपीसी के फंड को एचएसएम के खाते में स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था और ऐसा करने में उसने अवैधता की थी। इसी प्रकार, तीसरे आरोपी के पास पार्टी द्वारा प्रतिवाद के रूप में ईईपीसी के साथ एचएसएम के लिए या उसके कारण कार्य करने का कोई अधिकार नहीं था। एचएसएम द्वारा जारी किए गए अनुबंध नोट और डिलीवरी ऑर्डर, अनुबंध नोट पर और एचएसएम द्वारा जारी डिलीवरी आदेश , इसके विपरीत, यह दर्शाता है कि यूको बैंक प्रमुख था। ईईपीसी द्वारा जारी चेक भी यूको बैंक के पक्ष में थे। इन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट था कि ईईपीसी द्वारा यूको बैंक के पक्ष में जारी किए गए चेक केवल यूको बैंक के पक्ष में थे और उन्हें एचएसएम सहित किसी और के खाते में स्थानांतरित नहीं किया

जाना था। इसलिए, आरोपी के पास ईईपीसी के फंड को एचएसएम के खाते में स्थानांतरित करने या डायवर्ट करने का कोई अधिकार नहीं था और इसलिए, उसने अवैधता की थी, जाहिर तौर पर एचएसएम को उन फंडों का अनुचित आर्थिक लाभ देने के इरादे से। इसलिए, ये परिस्थितियाँ अभियुक्तों और एचएसएम के बीच आपराधिक साजिश को भी स्पष्ट रूप से स्थापित करती हैं। ईईपीसी के फंड को अवैध रूप से एचएसएम के खाते में स्थानांतरित करने का उद्देश्य, एचएसएम को भ्रष्ट या अवैध तरीकों से लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके आरोपी द्वारा अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना, लेनदेन को एचएसएम की प्रतिभूतियों के लेनदेन के रूप में दिखाना, जैसा कि छिपा हुआ है यदि लेनदेन यूको बैंक का था।"

10. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

11. अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया तर्क यह है कि विचाराधीन दस्तावेज मेहता द्वारा तैयार किए गए थे और पैसा ईईपीसी द्वारा मेहता को सौंप दिया गया था। ईईपीसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही अपीलकर्ता को कोई लाभ हुआ। अपीलकर्ता का कोई बेईमान इरादा नहीं था और उसने नियमित रूप से बैंक के अधिकारी के रूप में कार्य किया।

12. सीबीआई के विद्वान वकील ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।

13. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि टिकाऊ है।

14. हमने पाया कि निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं और रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से स्थापित हैं:

(I) ईईपीसी इंजीनियरिंग वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में सहायता के लिए वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य कर रही है। यह घरेलू निर्यातकों के लिए स्टील की कीमत को संतुलित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना संचालित कर रहा था। इसमें संवितरण के लिए धन था। इसके अलावा इसके पास कार्यालय की बिक्री के कारण भी धन था। आईपीआरएस का संचालन पीडब्लू 3, गिरीश चंद्र द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने यूको बैंक के पक्ष में तीन चेक के माध्यम से यूको बैंक में 7.75 करोड़ रुपये की राशि जमा की।

(ii) अपीलकर्ता ने यूको बैंक के सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए मेहता के खाते में राशि हस्तांतरित की, जो स्पष्ट रूप से ईईपीसी द्वारा किसी भी अधिकार के बिना मेहता के साथ मिलीभगत थी। उन्होंने ऐसी प्रतिभूतियों के अस्तित्व में आए बिना प्रतिभूतियों की भौतिक डिलीवरी के बदले में बैंक रसीदें जारी कीं।

(i i i) ईईपीसी ने कभी भी मेहता के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद का निर्देश नहीं दिया और न ही मेहता को संबंधित राशि के हस्तांतरण की अनुमति दी, लेकिन अपीलकर्ता के कहने पर ईईपीसी को गलत धारणा के तहत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।

15. पीडब्लू-3, गिरीश चंद्र, जिन्होंने ईईपीसी का प्रतिनिधित्व किया, ने बैंक के साथ जमा करने और किसी निजी पार्टी के पक्ष में उक्त राशि के डायवर्जन को अधिकृत नहीं करने के अभियोजन संस्करण का पूरी तरह से समर्थन किया। उक्त साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है। अपीलकर्ता ने मेहता के साथ साजिश करके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनाधिकृत रूप से मेहता के खाते में राशि जमा की। आरोपी ने प्रतिभूतियों के भौतिक अस्तित्व के बिना सुरक्षा लेनदेन के लिए बैंक रसीदें भी जारी कीं जो जालसाजी की श्रेणी में आती हैं। इस प्रकार, यह अनुमान लगाना सुरक्षित है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने मेहता के साथ साजिश रचकर और उसके लाभ के लिए पद का दुरुपयोग किया है। अभियुक्तों द्वारा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग जालसाजी/जाली दस्तावेजों का उपयोग करके आपराधिक विश्वासघात के साथ-साथ भ्रष्टाचार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध है। पीडब्लू-10, पिंजानी और पीडब्लू-12, श्रीमती किनी जो प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के लिए रजिस्टर का रखरखाव कर रही थीं, यह नहीं दिखा सकीं कि प्रश्नगत प्रतिभूतियां बैंक के पास

भौतिक रूप से उपलब्ध थीं, जब बैंक रसीदें आरोपी द्वारा जारी की गई थीं, जो केवल यदि प्रतिभूतियाँ उपलब्ध थीं किया जा सकता था। इस प्रकार विशेष न्यायालय ने आरोप को सही साबित किया। यह साबित करना जरूरी नहीं था कि आरोपी ने बैंक को कोई फायदा पहुंचाया या कोई नुकसान पहुंचाया। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता की कार्रवाई में सार्वजनिक धन का किसी व्यक्ति के निजी धन में अनधिकृत रूपांतरण शामिल था। प्रतिभूतियों के अस्तित्व के बिना प्रतिभूतियों के लिए बैंक रसीदें जारी करना किसी निजी व्यक्ति को अवैध लाभ के अलावा उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अभ्यास या उच्च अधिकारियों के निर्देश के नाम पर पेटेंट अवैधता का बचाव नहीं किया जा सकता है। मॉन्स रीम इस तथ्य से स्थापित होता है कि गैर-मौजूद प्रतिभूतियों के लिए झूठी बैंक रसीदें जारी की गईं।

16. इस प्रकार, साजिश, जालसाजी, हेराफेरी और भ्रष्टाचार के अपराध स्थापित होते हैं। उक्त अपराधों की सामग्री पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि इस मामले पर पहले ही अपीलकर्ता के संबंध में राम नारायण पोपली (उपरोक्त) में प्रकाशित किये गए फैसले में इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा चुका है। हम केवल उक्त मामले में निकले निष्कर्षों को उद्धृत कर सकते हैं:

"साजिश के अपराध के बारे में:

356. संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय और यशपाल मित्तल बनाम पंजाब राज्य [(1977) 4 एससीसी 540]-और अजय अग्रवाल बनाम भारत संघ [(1993) 3 एससीसी 609 में इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करने के बाद - महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा में न्यायालय - [(1996) 4 एससीसी 659] में - साजिश के आरोप को स्थापित करने के लिए कानून की स्थिति और आवश्यकताओं को संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है: (एससीसी पृष्ठ 668, पैरा 24)

"24- उपरोक्त निर्णय, भले ही वे वजनदार हों, हमें इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि साजिश का आरोप स्थापित करने के लिए किसी अवैध कार्य या अवैध तरीकों से कानूनी कार्य में लिप्त होने के बारे में ज्ञान आवश्यक है। कुछ मामलों में, गैरकानूनी उपयोग का इरादा होता है, प्रश्नगत वस्तुओं या सेवाओं से बने ज्ञान के आधार पर ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित नहीं करना है कि किसी विशेष गैरकानूनी उपयोग का इरादा था, जब तक कि प्रश्नगत वस्तुओं या सेवाओं को किसी भी वैध उपयोग में नहीं लाया जा सकता है अंत में, जब अंतिम अपराध में कार्रवाइयों की एक श्रृंखला शामिल होती है, तो अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना आवश्यक नहीं होगा कि साजिश का आरोप लगाया जाए, कि प्रत्येक साजिशकर्ता को यह ज्ञान था कि सहयोगी क्या

करेगा, इतने लंबे समय तक जैसा कि ज्ञात है कि सहयोगी सामान या सेवा का गैरकानूनी उपयोग करेगा।" [केरल राज्य बनाम पी. सुगाथन देखें-[(2000) 8 एससीसी 2031-(एससीसी पृष्ठ 212, पैरा 14)]

358. बहुत कुछ यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुनर्भुगतान किया गया है। यह अपने आप में बेईमान इरादे की कमी का संकेत नहीं है. कभी-कभी ऐसा होता है कि विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से पुनर्भुगतान किया जाता है ताकि भविष्य के लेनदेन के लिए पैसे का बेईमानी से दुरुपयोग किया जा सके। यह योजना का एक हिस्सा है और पुनर्भुगतान के तथ्य को अलग से नहीं माना जा सकता है। सॉलिसिटर-जनरल द्वारा उचित रूप से दावा किया गया पुनर्भुगतान सजा सुनाते समय विचार किया जाने वाला एक कारक हो सकता है, लेकिन आरोपी की बेगुनाही साबित करने का आधार नहीं हो सकता है।

.....

आपराधिक विश्वासघात के अपराध के बारे में:

361. विश्वास के आपराधिक उल्लंघन का अपराध गठित करने के लिए, एक सौंपा जाना चाहिए, किसी के स्वयं के उपयोग के लिए दुरुपयोग या रूपांतरण होना चाहिए, या कानूनी निर्देश या किसी

कानूनी अनुबंध के उल्लंघन में उपयोग होना चाहिए; और दुरुपयोग या रूपांतरण या निपटान बेईमान इरादे से होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति दूसरों को उसे सौंपे गए धन का दुरुपयोग करने की अनुमति देता है, तो यह धारा 405 द्वारा परिभाषित आपराधिक विश्वास उल्लंघन के बराबर होता है। यह धारा सकारात्मक भाग और नकारात्मक भाग में संपत्ति से संबंधित है। सकारात्मक भाग संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग या रूपांतरण से संबंधित है और नकारात्मक भाग में किसी भी निर्देश और कानून या विश्वास के निर्वहन से संबंधित किसी भी अनुबंध का उल्लंघन करके संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या निपटान शामिल है।

.....

जालसाजी के अपराध के बारे में:

374. जालसाजी का अपराध गठित करने के लिए दस्तावेजों को बेईमानी से या धोखाधड़ी से बनाया जाना चाहिए। लेकिन बेईमान या धोखेबाज़ तात्त्विक नहीं हैं। धोखाधड़ी का तात्पर्य संपत्ति से वंचित होना या चोट का कोई तत्व नहीं है। धोखाधड़ी करने के लिए, एक तरफ कुछ लाभ होना चाहिए और दूसरी तरफ उसी के अनुरूप नुकसान होना चाहिए। प्रत्येक जालसाजी एक झूठे दस्तावेज़ को या

तो पूर्ण या आंशिक रूप से प्रस्तुत करती है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो।

.....

377. आरोपी व्यक्तियों ने जिसे उन्होंने "बाजार प्रथाओं" के रूप में वर्णित किया है, उसके पीछे आश्रय लेने की कोशिश की है। ऐसी प्रथाएँ विद्यमान होने पर भी, वैधानिक और नियामक कार्यों का स्थान नहीं ले सकतीं। ऐसी प्रथाओं में कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है और ये नियामक या वैधानिक निर्देशों के अनुपालन का विकल्प नहीं हो सकते हैं। यह दिखाने का प्रयास किया गया कि बाद में बाजार प्रथाओं की अस्वीकृति हुई; जिस समय लेन-देन हुआ उस समय कोई प्रतिबंध नहीं था। उनका मानना है कि प्रथाएं स्वीकृत मानदंडों का हिस्सा थीं। हमें इन स्पष्टीकरणे में कुछ भी विश्वसनीय नहीं मिला। एक प्रथा भले ही प्रचलित थी, यदि गलत है, तो उसे अनुमोदित नहीं किया जाना चाहिए। बाद के स्पष्टीकरण किसी भी तरह से अतीत में अपनाई गई प्रथाओं पर अनुमोदन की मुहर नहीं लगाते हैं, दूसरी ओर इसकी निंदा करते हैं।

.....

भ्रष्टाचार अधिनियम के बारे में:

379. पीसी अधिनियम की धारा 13(2) का उद्देश्य लोक सेवकों की अनियमितताओं से निपटना है। इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि ए-1 ने, आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए, एक लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए ए-5 के गलत लाभ के लिए एमयूएल के धन का उपयोग करने और/या अनुमति देकर अपने पद का दुरुपयोग किया, धारा 13(1)(सी) सपठित धारा 13(2) के प्रावधान स्पष्ट रूप से लागू हैं। ए-3 की स्थिति भी ऐसी ही है।"

17. उपरोक्त के मद्देनजर, हम अपीलकर्ता की सजा में हस्तक्षेप करने में असमर्थ हैं। इसी बात की पुष्टि की गई है। हालाँकि, परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि यदि कारावास की सजा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि तक कम कर दिया जाए तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हम तदनुसार आदेश करते हैं।

18. अपील निस्तारित की गई।

देविका गुजराल

अपील निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।